बड़ा सोच

पीएम मोदी की जन्मतिथि पर कल पूरे हो रहे नई सरकार के सौ दिन, छह माह पहले शुरू हो गया था तीसरे कार्यकाल के लिए होमवर्क, कई महत्वपूर्ण निर्णयों से मिला संदेश, विकसित भारत के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी, किसान के साथ हर वर्ग को साधने का प्रयास

मोदी 3 .0 के लिए तैयार था ट्रैक, 100 दिन में ही पकड़ी सरकार ने रफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि पर पूरे हो रहे हैं। अभी सरकार जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रही है, उसका दूरगामी लक्ष्य तो 2047 तक विकसित भारत बनाने का बताया जाता है, लेकिन ट्रैक रिकार्ड स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल का रोडमैप बिल्कुल तैयार है। पहले 100 दिनों के लिए तो लोकसभा चुनाव के पहले से ही तैयारी चल रही थी। किसान और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए तो सरकार ने हाल में जो बड़े निर्णय लिए, ये छह महीने पहले से की गई तैयारी का ही नतीजा है। साथ ही सरकार ने महिला, युवा, अनुसूचित जाति-जनजाति से लेकर हर वर्ग को भी साधने का प्रयास किया है।

आम चुनाव में उतरने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के रोडमैप पर काम करने को कह दिया था। यह तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर उनका आत्मविश्वास ही था। इसलिए मोदी ने नौ जून, 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो तमाम मंत्रालयों ने 100 दिन के तैयार एजेंडे पर अमल शुरू कर दिया। सरकार की प्राथमिकताओं में किसान सबसे ऊपर हैं, इसका संकेत इस बात से मिलता है कि तीसरे कार्यकाल के पहले निर्णय में पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, डिजिटल कृषि मिशन सहित कई निर्णय किए।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक किसान सम्मान निधि तय करने से पहले एक अध्ययन कराया गया जिसमें पता चला कि लघु व सीमांत किसानों की कृषि लागत लगभग 5,600-5,700 रुपये आती है, जिसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। छह हजार रुपये सम्मान निधि देकर किसानों को इस संकट से उबारा।

प्रतीकात्मक

तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी

सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को वरीयता देते हुए तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। सामाजिक कल्याण की दृष्टि से पीएम जनमन योजना चल रही है। कचरा बीनने वालों के सशक्तीकरण के लिए उन्हें नमस्ते योजना में शामिल कराया। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन व संरक्षण को मजबूत करने और विवादों के निपटारे के लिए वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 भी लोकसभा में पेश हो चुका है। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का एलान हो गया है। कौशल विकास मिशन की निरंतरता बनाए रखते हुए 4.1 करोड़ युवाओं के कौशल सुधार और रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ का प्रधानमंत्री पैकेज बजट में घोषित किया। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, 28,600 करोड़ के निवेश संग 12 औद्योगिक नोड्स को मंजूरी व 10,600 करोड़ की विज्ञान धारा योजना जैसे फैसले लिए गए हैं।

नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए आवंटित किए तीन लाख करोड़ रुपये पेज>>5

देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना

केंद्र की तैयारी शुरू, जनगणना प्राधिकरण ने स्वगणना पोर्टल बनाया

दलों की मांग के बाद भी जातीय जनगणना पर फिलहाल फैसला नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने देश में जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जातीय जनगणना पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके जरिये नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है, जिसे अभी लांच नहीं किया गया है। स्वगणना के दौरान आधार नंबर या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाएगा। पूरी जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया पर 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना है।

एक सूत्र ने रविवार को अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि हर दशक में होने वाली जनगणना जल्द ही कराई जाएगी। लेकिन दशकीय जनगणना में जाति संबंधी कालम शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा, 'इस पर निर्णय होना अभी बाकी है।' राजनीतिक दल जाति जनगणना कराने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। नए आंकड़े नहीं होने के कारण सरकारी एजेंसियां अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बना रही हैं और सब्सिडी आवंटित कर रही हैं। भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण एक अप्रैल, 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।

जनगणना के लिए 31 सवाल किए गए तैयार

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने जनगणना के दौरान पूछने के लिए 31 सवाल तैयार किए हैं। इसमें पूछा जाएगा कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं और परिवार का मुखिया महिला है क्या। इसके अतिरिक्त परिवार के मुखिया अगर एससी/एसटी हैं तो यह जानकारी भी मांगी जाएगी। पूछेंगे कि एक परिवार के पास एक टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन है या नहीं। उनके पास वाहनों में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कार, जीप या वैन है या नहीं। पूछेंगे आप कौन सा अनाज अधिक खाते हैं। उनके पेयजल, बिजली, शौचालय, गंदे पानी की निकासी, रसोई और रसोई में एलपीजी/पीएनजी आदि की उपलब्धता की भी जानकारी ली जाएगी।

महिला आरक्षण भी जनगणना पर निर्भर

पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन भी इसी दशकीय जनगणना से जुड़ा हुआ है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने संबंधी कानून इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू होगा। जनगणना के तहत घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का कार्य एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

ऐसे की जाएगी गणना

- जनगणना पोर्टल खुल जाने के बाद, व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लागइन कर सकता है और अपना विवरण भर सकता है।
- जनगणना पोर्टल में व्यक्तियों को जनसंख्या गणना के लिए फार्म भरना होगा।
- विभिन्न विकल्पों को भरने के लिए स्क्रीन पर कोड डिसप्ले होंगे।
- एक बार स्व-गणना हो जाने के बाद, मोबाइल पर एक पहचान संख्या भेजी जाएगी।
- जब जनगणनाकर्मी घर-घर जाएंगे तो उनके साथ यह आईडी नंबर साझा किया जा सकता है, जो पहले से भरे हुए सभी डेटा को अपने आप आनलाइन सिंक कर देगा।

निर्मला सीतारमण ने की थी डिजिटल जनगणना की घोषणा

एक फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में डिजिटल जनगणना किए जाने की घोषणा की थी। साथ ही बजट में इसके लिए 3,726 करोड़ रुपये भी आवंटित किए थे। जुलाई 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया था कि कोरोना महामारी की वजह से 2021 की जनगणना और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

आर्थिक कुप्रबंधन से निकलने की राज्यवार नीति हो प्राथमिकता

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

- राज्यों को तात्कालिक और दीर्घकालिक कदमों पर एक साथ काम करने की जरूरत
- खर्च घटाने के साथ-साथ विनिवेश, जमीन के व्यावसायीकरण जैसे कदमों पर विचार

नई दिल्ली : भारत जितनी विविधता वाला देश है, इसके राज्यों की आर्थिक स्थिति भी उतना ही विविध रंग लिए हुए है। पिछले दो आलेखों में यह स्पष्ट दिखा कि खजाने की कीमत पर राजनीति और प्रशासकीय शिथिलता के कारण कुछ राज्य निवेश आकर्षित करने में, राजकोषीय घाटा कम करने में, बाहरी कर्ज का बोझ कम करने, प्रतिव्यक्ति आय जैसे मापदंडों पर पिछड़ते जा रहे हैं, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जो इन सभी मानदंडों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। नतीजा यह है कि राज्यों के बीच आर्थिक फासला भविष्य में और बढ़ने के संकेत हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, बैट्री निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा से जुड़े उद्योग का आकर्षण सिर्फ गुजरात, तमिलनाडु व कुछ हद तक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक ही सीमित रहा है, वह इसका उदाहरण है।

दूसरी तरफ कुछ राज्य खुलकर अपना खजाना खाली दिखा रहे हैं। इन हालात में विशेषज्ञों का कहना है कि हर राज्य के वित्त की अपनी मजबूती व खामियां हैं और इसके आधार पर ही इनकी आर्थिक नीतियों को बनाना होगा। यह काम और इसकी प्लानिंग जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो वर्ष 2047 में जब भारत एक विकसित देश होगा तब भी इसके कुछ राज्य 'बीमारू' होने का तमगा पहने होंगे।

वित्त मंत्रालय के पूर्व आर्थिक सलाहकार व नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार कहते हैं कि राज्यों को खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कुछ कदम तत्काल उठाने होंगे और कुछ दीर्घकालिक होंगे। जिन राज्यों की वित्तीय स्थिति लचर है उन्हें गैरजरूरी खर्चों पर तत्काल लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्यों को निजी निवेश बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश करना होगा।

कर्ज कम नहीं किया तो नहीं होगा सरकार चलाने के लिए पैसा : सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य विशेष के लिए किसी बेल आउट पैकेज जैसी व्यवस्था की संभावना तो नहीं है। प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में जरूर वित्तीय पैकेज दिया जाता है। ऐसे में राज्यों को तात्कालिक रूप से जो कदम उठाए जाने चाहिए उसमें विनिवेश और मौद्रिकीकरण है। जो सरकारी उपक्रम फायदेमंद नहीं है, उसका विनिवेश किया जाए। संपदा के मौद्रिकीकरण के साथ वे घाटे में चल रहे अपने उपक्रमों को बेचकर राजस्व अर्जित कर सकते हैं। राज्यों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है जिसका वाणिज्यिक उपयोग कर राजस्व बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इन माध्यम से जो राजस्व मिले उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाए। इन राशियों का कहीं और इस्तेमाल करने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। कर्ज कम करने की कोशिश अगर राज्यों की तरफ से नहीं होती है तो एक समय ऐसा आएगा कि इनके पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं बचेगा।

मुफ्त में कोई और सेवा दी तो स्थिति बदतर होगी : आरबीआइ

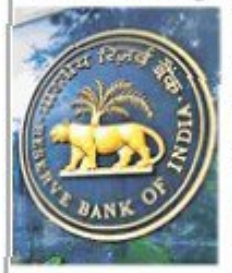

हाल ही में जब पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति चरम पर थी और राज्य चुनावों में इसे सत्ता पर दोबारा काबिज होने के ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही थी, तब आरबीआइ ने चेताया था कि यह राज्यों के वित्तीय बोझ को 4 .5 गुणा तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय बैंक ने इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की वकालत की थी। आरबीआइ का मानना है कि राज्य अगर अब कोई भी नई गैर वाजिब सेवा मुफ्त में देते हैं या सब्सिडी, फंड ट्रांसफर की घोषणा करते हैं तो इससे उनकी कुल आर्थिक स्थिति बदतर ही होगी। स्पष्ट है कि एक ऐसा दौर आ चुका है जब केवल सत्ता में आसीन दल को ही नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों को ऐसी राह चुननी होगी जो जनकल्याणकारी होने के साथ राज्य के वित्तीय हित में हो। यानी इस विषय पर पक्ष और विपक्ष को एक बिंदु पर आना होगा।

भारत और मालदीव ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं...

माले, प्रेट्र : भारत और मालदीव ने कुछ गलतफहमियों के बाद अब अपने मतभेद सुलझा लिए हैं। ये मतभेद राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जू सरकार के शुरुआती दिनों में पैदा हुए थे। यह बात मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने श्रीलंका यात्रा के दौरान कही है।

मालदीव के विदेश मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र के पड़ोसी देशों के बीच बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए भारत और चीन से मजबूत रिश्तों की इच्छा जताई। कहा, मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर भारत के साथ उनके देश के संबंधों में थोड़ी कटुता पैदा हुई थी लेकिन सैनिकों की वापसी के बाद अब वह खत्म हो गई है। एक अखबार से साक्षात्कार में जमीर ने स्वीकार किया कि मुइज्जू सरकार के शुरुआती दिनों में भारत के साथ संबंधों में कटुता आ गई थी। लेकिन अब भारत और चीन के साथ मालदीव के अच्छे रिश्ते हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट का नारा लगाने के बाद जब मुइज्जू राष्ट्रपति बने और कुछ ही घंटे बाद मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए कहा तो दोनों देशों के संबंधों में कटुता पैदा हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों की वार्ता में बनी सहमति पर सैन्य कर्मियों की जगह नागरिक सेवा के कर्मियों की मालदीव में नियुक्ति हुई। भारत ने पूर्व में मालदीव को विभिन्न सुविधाओं में उपयोग के लिए तीन हेलीकाप्टर और विमान उपहार स्वरूप दिए थे। उन्हीं के संचालन के लिए वहां पर सैन्यकर्मी तैनात थे।

द्वीपीय देश के विदेश मंत्री जमीर ने माना-कुछ गलतफहमियां थीं

मुइज्जू सरकार ने कहा, भारत व चीन के साथ अच्छे संबंधों के हैं इच्छुक

परिवर्तन महारैली • भारी बारिश के बीच सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे पीएम

झारखंड के तीन दुश्मन, झामुमो-कांग्रेस और राजद : प्रधानमंत्री

भास्कर टीम| जमशेदपुर/ रांची

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। मूसलाधार बारिश के बीच वे सड़क मार्ग से रांची से जमशेदपुर पहुंचे। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में परिवर्तन महारैली को संबोधित किया। अपने 40 मिनट के भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार, घुसपैठ, सीएम मंईयां सम्मान योजना और उत्पाद सिपाही बहाली पर झारखंड सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने कहा-झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं-झामुमो, कांग्रेस और राजद। कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इन दुश्मनों को पहचानिए।

कांग्रेस ने कई दशक तक दिल्ली में बैठकर राज किया। दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। मोदी ने कहा कि झामुमो के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। घुसपैठिए व कट्टरपंथी झामुमो को कब्जे में लेते जा रहे हैं। झामुमो में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस पार्टी का इकलौता एजेंडा बन जाता है। ऐसे लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। झामुमो का भी ऐसा ही हाल हो रहा है। शेष पेज 13 पर

पीएम ने किया उद्घाटन, पटना पहुंची ट्रेन

पटना-टाटा वंदेभारत: तीन ट्रेन नंबर, दो रूट पर चलेगी... किराया 1280 से 3225 के बीच

पटना | टाटा-पटना के बीच वंदे भारत सप्ताह में 6 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को चलेगी। सोमवार और रविवार को ट्रेन का परिचालन बरकाना रूट से होगा। पटना से खुलने और पहुंचने का समय भी अलग होगा। मंगलवार को यह ट्रेन दोनों ओर से नहीं चलेगी। रूट बदलने के साथ ट्रेन नंबर, सफर का समय और ट्रेन का किराया भी बदल जाएगा।

रात 8.20 बजे पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर वंदेभारत पहुंची। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सांसद रविशंकर प्रसाद, डीआरएम और सिनियर डीसीएम ने ट्रेन का से स्वागत किया।

20893/20894

टाटा से 5:30 बजे सुबह खुलेगी, 12.45 बजे पटना पहुंचेगी। **रूट-** चांडिल, मुरी, बोकारो, गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, पटना। इस रूट पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार चलेगी। पटना से 2:15 बजे खुलेगी। 9:30 बजे टाटा पहुंचेगी।

किराया	
चेयर कार	एग्जीक्यूटिव
₹1505	₹2570

21893/21894

रविवार को टाटानगर से सुबह 5.30 बजे खुलेगी। दोपहर 3.55 बजे पटना पहुंचेगी। **रूट-** चांडिल, मुरी, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, गढवा, सोननगर, गया, पटना। सोमवार को पटना से दोपहर 1.20 बजे खुलेगी। टाटा रात 11.55 बजे पहुंचेगी।

किराया	
चेयर कार	एग्जीक्यूटिव
₹1825	₹3225

21895/21896

यह सोमवार और रविवार को चलेगी। टाटा से सुबह 5.30 बजे खुलेगी। **रूट-** चांडिल जंक्शन, मुरी, बोकारो, गोमो, कोडरमा, गया, पटना। 12.45 बजे पटना पहुंचेगी। शाम 4:45 बजे पटना से खुलेगी। टाटा रात 11.55 बजे पहुंचेगी।

किराया	
चेयर कार	एग्जीक्यूटिव
₹1280	₹2325

Will quit in two days, announces Kejriwal

Agencies
letters@hindustantimes.com

Delhi chief minister and Aam Aadmi Party (AAP) national convener Arvind Kejriwal addresses the party supporters, in the presence of party leaders, in New Delhi on Sunday. ANI

NEW DELHI: Delhi chief minister Arvind Kejriwal on Sunday announced that he would resign after two days and sought early polls in the national capital while vowing not to sit in CM's chair till people give him a "certificate of honesty".

The BJP hit back at the AAP supremo, terming his move a "PR exercise" and a "drama".

Kejriwal, released on bail from Tihar on Friday in the excise policy case, said he would hold a meeting of AAP MLAs in the next couple of days and a party leader would take over as chief minister.

The AAP national convener, who reached the party headquarters here on Sunday along with his wife Sunita to address party workers, said he would become chief minister and Manish Sisodia deputy CM "only when people say we are honest".

Sisodia got bail in the excise policy case last month.

Following Kejriwal's unexpected announcement, the names of his wife Sunita and Delhi ministers Atishi and Gopal Rai as his probable replacement are doing the rounds.

"I am going to resign after two days and ask people whether I am honest. Till they respond, I won't sit on CM's chair," Kejriwal said.

"Delhi elections are due in February but I demand that the elections in the national capital be held in November along with Maharashtra... I will only sit on CM's chair after people give me a certificate of honesty. Want to give 'agnipariksha' (trial by fire) after coming out of jail."

Alleging the BJP tried to prove him corrupt, Kejriwal claimed that the party could not provide good schools and free electricity to people because they were corrupt. "We are honest," he asserted.

"They slap false cases against non-BJP chief ministers. If the CMs are arrested, I urge them not to resign but run their government from jail," the Delhi chief minister said.

"I didn't resign (after arrest in excise policy case) because I respect democracy and the Constitution is supreme for me," Kejriwal said and asserted that it is only the AAP that can stand

continued on →7

Nipah death confirmed in Malappuram; 150 contacts asked to isolate themselves

The Hindu Bureau
MALAPPURAM

Sale of masks has picked up pace near a Kozhikode hospital in the wake of the Nipah death in Malappuram. K. RAGESH

Health authorities in Kerala on Sunday confirmed that a 24-year-old man from Wandoor in Malappuram district in the State had died from Nipah infection on September 9.

Health Minister Veena George said tests at the National Institute of Virology, Pune, had confirmed it to be a Nipah case.

The man, a student in Bengaluru, died in a private hospital at Perinthalmanna after being admitted with hepatitis symptoms. Nipah was suspected after he showed symptoms of encephalitis.

The health authorities sent his serum samples to the virology laboratory at the Government Medical College Hospital, Kozhikode. On Saturday evening, the lab revealed that the samples had tested positive.

The Health Department swung into action by following the Nipah protocol. While the department waited for final confirmation from the Pune institute, 16 committees were formed under the protocol at night.

Contact list

District Medical Officer R. Renuka said the man had sought treatment at four private hospitals, and had travelled to different places along with his friends.

Hence, as many as 150 persons were identified in the victim's primary contact list and instructed to isolate themselves.

As five of them had shown mild symptoms, their samples were sent for testing.

Dr. Renuka said all persons likely to have come into contact with the victim were being traced and observed, adding that there was no need to worry.

On July 21, a 14-year-old boy from Pandikkad, about 10 km from Wandoor, had died from Nipah infection at the Government Medical College Hospital, Kozhikode. The boy's death had triggered an alarm across the district, and authorities had imposed restrictions in two panchayats.

Democratic engagement with a digital plug-in

Sanjay Kumar

Professor at the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) and a political commentator

Abhishek Sharma

researcher at the Lokniti-CSDS and a candidate at the Department of Political Science, University of Delhi

Imagine a summer evening in the United Kingdom, right before the Brexit referendum. Social media was flooded with posts and advertisements, each one more eye-catching than the other. But among these, a campaign called 'Leave.EU' began to stand out. The messages played on fears, hopes, and a sense of lost identity. 'Leave.EU' harnessed digital platforms to target individuals with calculated and data-driven content, shaping their perceptions and pushing them towards voting to leave the European Union.

Today, as we look back at the Brexit referendum, it serves as a potent reminder of how the structure of democracy is increasingly being defined by technology. Digital platforms, once seen as great equalisers that empowered the masses and amplified previously unheard voices, have become a double-edged sword. We see a similar trend in India where digital campaigns are now central to electoral strategies not only by national parties but even by regional parties. The same tools that can empower voters can also distort public discourse, as shown by the growing use of digital political advertisements by political parties. This was highlighted by the Lokniti-Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) studies on digital campaigns during the 18th election to the Lok Sabha (April–June 2024).

The economics

The expenditure reports from the 2023 Karnataka Assembly election clearly illustrate the translation of economic power into digital influence. The Bharatiya Janata Party (BJP) spent ₹7,800 lakh on digital advertisements, which is 52% of its total "party propaganda" budget. The Indian National Congress, on the other hand, spent ₹4,900 lakh, which is 55% of its total "party propaganda" budget. Conventional tools of publicity or propaganda such as flags, billboards, public meetings, and rallies, made up only 16% of the BJP's and 7% of the Congress's total propaganda spending. This shows a strategic shift toward digital platforms in the electoral strategies of political parties. Further underscoring this trend, the BJP became the first Indian political party to spend over ₹116 crore on Google ads in just five months, from January 2024. During the 2024 general election period from April 19 to June 1, 89,000 advertisements posted by the BJP were running on Google, on which more than ₹68 crore was spent. In contrast, 2,900 advertisements posted by the Congress were running during the same period, on which over ₹33 crore was spent.

An additional layer to this digital strategy is the use of micro-targeting, based on location, with parties reaching specific audiences all the way down to the panchayat level in each advertisement. The BJP, for instance, was found to micro-target more than 1,700 pin codes in a single advertisement, demonstrating the profound capability of digital platforms in shaping electoral narratives with precision. This new frontier in political campaigning, where financial resources translate directly into targeted digital influence, marks a transformative shift in the democratic process.

This new frontier in political campaigning marks a transformative shift in the democratic process, but the rulebook remains stuck in the past

The narrative

While the financial clout of major political parties is well documented, a more insidious force, or third-party campaigners, operates in the background. Although the information on Google Ads expenditure is publicly accessible, there is another ship at play, one not merely loaded with funds but armed with a potent mix of influence and manipulation – quietly anchored at the "offshore islands of parties," and far from scrutiny and oversight. These 'offshore islands' represent third-party campaigners, a new phenomenon in Indian elections.

Another study conducted by the Lokniti-CSDS, analysing 31 third-party campaigners on Meta, showed that these entities spent over ₹2,260 lakh in just 90 days leading up to June 29, 2024. This brings up important questions about the motivations behind such substantial financial outlays. What makes these groups spend so much money on campaigns for certain parties or candidates? The *modus operandi* of these campaigners suggests a possible and covert *quid pro quo* with political parties, where the parties might be pulling the strings from behind.

Moreover, the content propagated by these campaigners is often more alarming than the money they spend on it. The study found that third-party campaigners also resorted to using Islamophobic language and derogatory slurs in their political advertisements. This contrasts sharply with the content of political advertisements posted by the official parties on Google, which, while critical, generally refrained from such inflammatory rhetoric. The proliferation of such content by third-party actors not only distorts the democratic discourse but also raises ethical and regulatory questions about the role of these entities in electoral processes. These entities blur the fine line between persuasion and manipulation, casting a shadow over the integrity of democratic engagement.

This discussion points to three major issues that are emerging in the realm of digital campaigning that demand urgent attention: regulation of expenditure; content oversight, and the challenges posed by platformisation. First, the disparity in financial resources among political parties is manifested by their digital advertisement spending, particularly on platforms such as Google. Wealthier parties can dominate the digital landscape, creating an uneven playing field for existing and emerging players. This highlights the urgent need for 'segmented caps' on party expenditure, which would not only limit overall spending but also ensure balanced allocation across various campaign categories, such as digital campaigns and rallies..

Second, content regulation is brought into focus by the role of third-party campaigners. There must be strict expenditure reporting requirements for these non-contestants, similar to practices in the United Kingdom and Canada. Additionally, an independent agency should conduct an audit of their content after each election cycle to balance the right to free speech with the need for effective oversight. This audit would go beyond the current role of the Media Certification and Monitoring Committee (MCMC), which has proven to be less than ideal.

Lastly, platformisation has led to varied content strategies across digital platforms. For instance, on Google, political advertisements by parties and third-party campaigners typically avoid overtly derogatory content, and there was no significant spending by third-party campaigners. In contrast, on Meta, a large number of third-party campaigners were among the top spenders, often featuring inflammatory or problematic content in their political advertisements. This disparity highlights the need for uniform, harmonised regulatory frameworks to tackle problematic digital content across platforms, which will also ensure that all tech giants are held to the same standards of accountability.

Need for reforms

In the digital age, the rules of the game have changed, but the rulebook remains stuck in the past, leaving regulatory loopholes and shortcomings. The task before us is to navigate this complex terrain, ensuring that technology serves to enhance, rather than erode, the democratic ideals that we hold dear. This can only be achieved through comprehensive studies in India's context, particularly in the emerging field of digital campaigning. To come up with robust solutions, we must move beyond the constraints of traditional political theories and build a body of literature that unravels the layers of the digital realm.

International Day of Democracy, celebrated globally on September 15 each year, has passed, but it is crucial to push for reforms that expand the definition of rule of law to encompass the digital realm. This expansion can ultimately bring the value of delight to our democracy by forging effective regulations in the domain of the digital.

The views expressed are personal